सं0-15 / 934/12-3-2014-100(51)2012

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 09 जुलाई, 2014**

विषय:- कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये कृषि प्रसार, कृषि निवेश तथा तकनीकी प्रबन्धन की योजना के अन्तर्गत संचालित उप योजनाओं हेतु वर्ष 2014-15 हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-प्रसार/04/तकनीकी प्रबंधन योजना/ 2012-13, दिनांक 2.4.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये कृषि प्रसार, कृषि निवेश तथा तकनीकी प्रबन्धन की योजना के अन्तर्गत संचालित उप योजना कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम हेतु वर्ष 2014-15 में व्यय हेतु रू0-67751 हजार (रू0 छः करोड़ सतहत्तर लाख इक्यावन हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण के अनुसार आपके निस्तारण पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र.स.	मानक मद	वर्ष **2014-15** के लेखानुदान में प्राविधान	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	02-मजदूरी	3539	1179
2	04-यात्रा व्यय	2285	761
3	08-कार्यालय व्यय	1995	665
4	09-विद्युत देय	750	250
5	11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1550	517
6	13-टेलीफोन पर व्यय	3525	1175
7	14-मोटर गाड़ियों का क्रय	-	-
8	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	6925	2308
9	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	180	60
10	29-अनुरक्षण	1070	357
11	31-सामग्री और सम्पूर्ति	380	127

http://shasanadesh.up.nic.in

12	42-अन्य व्यय	180470	60157
13	44-प्रशिक्षण	-	-
14	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्ट्वेयर का क्रय	110	37
15	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	475	158
	योग	**203254**	**67751**

(रू0 छः करोड़ सतहत्तर लाख इक्यावन हजार मात्र)

2- उक्त धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय होने के उपरान्त द्वितीय किश्त आहरित की जायेगी।

3- उक्त धनराशि का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश, बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैंड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी है उन मामलों में व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4- उक्त धनराशि शासनादेश संख्या-934/12-3-2014-100(51)/2012, दिनांक 13.6.2014 द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार व्यय की जायेगी। उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है। उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजना की प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़वा मिलता है।

6- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1- 1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने

http://shasanadesh.up.nic.in

की व्यवस्था दिनांक 1.4.2013 से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय।

8- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

9- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक- 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-109-विस्तार तथा किसानों केा प्रशिक्षण-07-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि प्रसार, कृषि निवेश तथा तकनीकी प्रबंधन की योजना के सुसंगत मानक मदों अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14.3.2014 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल **)**
संयुक्त सचिव।

<u>सं0-934(1)/12-3-2014-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालाय, कृषि भवन, लखनऊ।
6- संयुक्त कृषि निदेशक (ब्यूरो) कृषि भवन, लखनऊ।
7- संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन) कृषि भवन, लखनऊ।
8- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल **)**
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in